

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY)

प्रलिमिस के लिये:

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन, वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC)।

मेन्स के लिये:

भारत की खाद्य सुरक्षा पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) का प्रभाव।

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) को दसिंबर 2022 तक (और तीन महीने के लिये) वसितारति करने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY):

- परिचय:
 - 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' को [कोवडि-19](#) के बुरुद्ध लड़ाई में गरीब और संवेदनशील वर्ग की सहायता करने के लिये 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज' (PMGKP) के हसिसे के रूप में शुरू किया गया था।
 - इस योजना के तहत [सार्वजनिक वितरण प्रणाली \(PDS\)](#) के माध्यम से पहले से ही प्रदान किया जा रहे 5 कलिंगराम अनुदानति खाद्यानन के अलावा प्रत्येक दयकताको [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम \(NFSA\), 2013](#) के तहत 5 कलिंगराम अतिरिक्त अनाज (गेहूँ या चावल) मुफ्त में उपलब्ध कराने का लक्षण निर्धारित किया गया है।
 - परारंभ में इस योजना की शुरआत तीन माह (अप्रैल, मई और जून 2020) की अवधि के लिये की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्डधारक शामिल थे। बाद में इसे सर्तिंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
 - वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है।
 - देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के तहत कोई भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी पोर्टेबलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठा सकता है।
- लागत: सभी चरणों के लिये PMGKAY का कुल खर्च लगभग 91 लाख करोड़ रुपए होगा।
- चुनौतियाँ: एक प्रमुख मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी अंतमि जनगणना (2011) पर आधारित हैं, हालाँकि तिब से खाद्य-असुरक्षा से जुड़े लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि अब इस योजना के तहत शामिल नहीं हैं।
- मुद्दे:
 - महँगा: सस्ते अनाज की प्रचुर आपूर्ति की आवश्यकता को बनाए रखना और बढ़ाना सरकार के लिये बहुत महँगा है। वर्ष 2022 में भारत को गेहूँ और चावल के नियात को प्रतिबंधित करना पड़ा, क्योंकि अनशिक्ति मौसम के कारण फसल को नुकसान हुआ, खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ गया, वैश्वकि कृषि बाजारों में संकट की स्थिति देखी गई।
 - राजकोषीय घाटे में वृद्धि: यह राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक सीमित करने के सरकार के लक्ष्य के लिये जोखिमि उत्पन्न कर सकता है।
 - मुद्रास्फीति
 - कार्यक्रम में लिये गए नियन्य मुद्रास्फीति को भी प्रभावित कर सकते हैं। चावल और गेहूँ की कीमतें जो कि भारत की खुदरा मुद्रास्फीति का लगभग 10% हसिसा हैं, लू के प्रकोप और अनियमित मानसून के कारण इनके उत्पादन में कमी आई है तथा इसी वजह से उनकी कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है।

सरकार की संबंध पहलें:

- [राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मशिन](#)

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)
- तलिहन, दलहन, पाम और मोटे अनाज पर एकीकृत योजनाएं (ISOPOM)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

प्रश्न:

प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की मुख्य वशिष्टताएँ क्या हैं? खाद्य सुरक्षा विधियक ने भारत में भुखमरी और कृपोषण को खत्म करने में कैसे मदद की है? (2021)

स्रोत : द हिंदू

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/pradhan-mantri-garib-kalyan-anna-yojana-3>

